INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2024; 6(1): 105-110
Received: 06-01-2024
Accepted: 09-02-2024

Rupak Kumar
Ph.D., Department of History, University of Delhi, Delhi, India

Corresponding Author:
Rupak Kumar
Ph.D., Department of History, University of Delhi, Delhi, India

नैतिकता और राजनितिक अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में उत्तर पश्चिमी प्रान्त का आकाल: 1868-1870

Rupak Kumar

DOI: https://doi.org/10.22271/27069109.2024.v6.i1b.269

सारांश:
इस लेख में उत्तरी पश्चमी प्रान्त में 1868-1870 के आकाल के विशेष संदर्भ में नैतिक, राजनितिक प्रक्रियाओं और ब्रिटिश राज के राजनितिक अर्थव्यवस्था के परस्पर क्रिया और उनसे गुंथी हुई सामजिक आर्थिक सह-संबंधों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, जिससे 19वीं सदी के अंतिम दौर में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त ने आकाल और सूखा जैसी समस्याओं का सामना किया. वस्तुतः यह सदी क्रमिक और बारम्बार आकाल और सूखा का दौर था[1]. विशेष रूप से 1850-1900 का काल भारतीय इतिहास में 50 वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा बार आकाल और सूखा की समस्या से जूझने वाला समय था, जिसमें न केवल बड़ी संख्या में भोजन की कमी से लोग की मौतें हुई बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के प्रवसन, भूखमरी, बीमारियों, कुपोषण आदि जैसे अनेक समस्याओं का सामना किया. इन आकालों का विस्तृत विवरण फेड्रिक हेन्वी द्वारा संकलित रिपोर्ट "ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869 एंड द बिगनिंग ऑफ़ 1870" में मिलता है. इस रिपोर्ट को ही आधार बनाते हुए इस लेख के द्वारा ब्रिटिश शासन व्यावस्था का समालोचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है.

कूटशब्द : आकाल, सूखा, नैतिकता, उत्तरी पश्चमी प्रान्त, राजनितिक प्रक्रिया, समाजिक आर्थिक सहसंबंध

प्रस्तावना
आकाल किसान समाज का केंद्रीय विषय है और भारत में इस विषय पर शोध की कमी नही है. रोमेश चन्द्र दत्त जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा विकसित औपनिवेशिक साम्राज्य की आलोचना के लिए आकाल को केंद्रीय विषय बना ब्रिटिश साम्राज्य के शोषणकारी नीतियों के आलोचना की गयी. लेट विक्टोरियन होलोकास्ट में माइक डेविस लिखते हैं कि जब शांतिकालीन आकाल पश्चमी यूरोप से व्यवहारिक रूप से गायब हो गये तो यह विनाशकारी रुप से औपनिवेशिक दुनिया के अन्य हिस्सों में बढ़ गये.

माइक डेविस ने दिखाया है की महान आकाल विक्टोरियन युग में साम्राज्य के इतिहास से गायब पन्ने या अनुपस्थित परिभाषा के क्षण है.[2] यह पर यह गौर करने वाला विषय है की औपनिवेशिक दस्तावेजों में आभाव, कमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नही किया गया बल्ब्की इस्नके जगह सूखा शब्द क इस्तेमालकिया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह शासन का विषय तो था ही साथ ही साथ एक औपनिवेशिक संहिताकरण जैसे क़ानूनी विषय भी था.

उत्तरी पश्चिमी प्रान्त में सामराजी दस्तूर में 1857 की क्रांति के बाद परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ. वास्तव में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त में शामिल मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद, बनारस, रोहेलखंड आदि जिले 1857 की क्रांति का केंद्र रहे थे. उपनिवेशी शासन के दौर जहाँ एक और हमें संचार क्रांति के रूप में स्वेज कैनाल के खुलने, रेलवे का विकास, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण और ब्रिटेन में बढती समृद्धि देखने को मिलता है तो दूसरी और इस समय हमें भारत के कई जिलों में आकालों, निर्धनता के और भी स्पष्ट अंतर, शासन और शासित के बीच बढ़ते भेद, लोगों का पलायन, देखने को मिलता है. वस्तुतः इस समय दूसरी ओर ब्रिटिश आर्थिक परिणामों की आलोचना भी देखने को मिलता है.[3]

वास्तव में इस समय विभिन्न जिलों में सूखा और आकाल का कारण अनियमित कालीन वर्षा, पानी कि अनुपलब्धता के कारण फसलों कि बर्बादी और सबसे मुख्य रूप से भारतीय मानसून प्रणाली को दोषी माना गया है. परन्तु इस प्रान्त की भौगोलिकताओं, उत्पादन और उपभोग क्षमता और भू-विवधता के कारण हर जिलों में इसके अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता जैसे की तराई क्षेत्र बनारस और इलाहाबाद में झाँसी, अजमेर, बुंदेलखंड के मुकाबले जीवन निर्वाह के संकट का कम था. इस दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि यह एक प्रकार की मानव जनित आपदा थी, जिसमें अनगिनत लोग एवं मवेशी मौत के मुंह में समा गये, और इस भयावह परिस्थिति में भोजन और जीवन निर्वाह तलाश में एक बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, जो भौगौलिक विशेषताओं और उत्पन्न संकटों और ब्रिटिश राज की प्रशासनिक विफलता की और इशारा करता है. इन संकटों के लिए औपनिवेशिक शासन प्रणाली की राजस्व नीतियाँ, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, आधुनिक कृषि प्रणाली, और एक बड़ी मात्रा में खाद्यान फसलों की निर्यात पद्धति जिम्मेदार थी. जब हम ब्रिटिश राज कि राजनैतिक अर्थव्यवस्था पर गौर करते हैं तो इस रिपोर्ट से हमें उनके आर्थिक पक्षों का पलड़ा सामाजिक और नैतिक पक्षों से ज्यादा भारी दिखायी पड़ता है.

इस रिपोर्ट में जलवायु कारकों पर हरेक अध्याय में प्रकाश डाला गया है जिसमें यह बताया गया है की वर्ष में तीन महीने मानसूनी वर्षा के बाद शेष मौसम शुष्क रहता है. शुष्क मौसम में पानी की का सैधांतिक समाधान कुएं थे जिनकी पूंजीगत लागत, और जोखिम काफी कम था साथ ही कुओं ने नहरों और तालाबों से जुड़े वाष्पीकरण और रिसाव के नुकसान से भी बचाया[4]. ये नहरों का विकल्प तो नही बल्कि पूरक थी. इस संदर्भ में इस रिपोर्ट में नहरों और तालाबों के निर्माण पर कुओं के निर्माण से ज्यादा जोड़ दिया गया जबकी विपरीत परिस्थितियों में यह कृषकों के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ और जीवन निर्वाह के उत्पादन में काफी महत्व रखता था[5]. आकाल से जुडी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य जैसे रेलवे, नहरों, बांधों, आदि के निर्माण की शुरुआत की गयी जिसका सम्बन्ध लोगों के जीवन की रक्षा से ज्यादा औपनिवेशिक रणनीतियों का हिस्सा नज़र आती है.

शासित के नज़रों में ब्रिटिश राज के शासन की वैधता स्थापित करने के लिए तथाकथित लोकोपकारी कार्य धरातल पर कितने वास्तविक

और और नैतिक थे, यह भी गौर करने वाला विषय है. इस रिपोर्ट में आकाल से जुड़े जनहानि के मुद्दे, सूखा बचाव कार्य, राजस्व माफ़ी, कृषकों को अग्रिम राशि, सिंचाई के माध्यम से सूखा को रोकना, बढ़ते अपराध को रोकने के उपाय, और आवर्जन से जुड़े मुद्दे देखने को मिलते हैं. वास्तविक तौर पर सहायतार्थ कार्य हर जिले में भिन्न भिन्न थे और उसका कोई केंद्रीय स्वरुप नहीं था साथ ही सार्वजनिक कार्य, रेलवे, बांधों नहरों का निर्माण, और पुअर हाउस जैसे संविदात्मक कार्य साम्राज्यवादी विचारधारा और औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली से प्रभावित थे.

इस प्रान्त में मजदूर वर्गों की संख्या लगभग 7.5 लाख[6] थी जो बड़ी संख्या में भूखमरी से जूझ रहे थे और ये गरीब मजदूर श्रम के न्यूनतम मूल्यों पर सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे सार्वजनिक कार्य करने के लिए मजबूर थे. श्रमिकों की मजदूरी भी अलग अलग जिलों में श्रम की उपलब्धता और आकाल की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न थी जैसे की आगरा नहर के निर्माण में लगे मजदूर को प्रतिदिन 2 आना 5 पैसे, ईस्टर्न गंगा नहर में पुरुषों को 1.5 आना और महिलाओं को 1 आना, तो झाँसी में यह दर और भी कम थी, जबकि मेरठ में यह 3 आना 3 पैसे था[7]. इस कारण वर्षा के आगमन और कृषि कार्यों के शुरुआत के साथ ही इन सार्वजनिक कार्यों में मजदूरों की संख्या विभिन्न जिलों में घटती नज़र आती है. यहाँ पर यह भी गौर करने वाला विषय है कि ये मजदूर समाज के निचले तबके से सम्बन्ध रखते थे एवं भूमिविहीन थे.[8] ओडिशा आकाल आयोग के रिपोर्ट में यह भी जिक्र मिलता है कि ''यह खाद्यान का संकट नही था बल्कि मजदूरी की उपलब्धता का संकट था'. अमर्त्य सैन ने आकाल का परिष्कृत सिद्धांत इसी आधार पर प्रस्तुत किया जो लोगों के भोजन की उपलब्धता और अन-उपलब्धता क्रय शक्ति के बीच के संबंधो पर आधरित था[9]. प्रान्त में आकाल के कारण कृषिगत उपज के नष्ट होने और मजदूरी की दरों के कम होने से लोगो के क्रय करने की क्षमता पर असर पड़ा इस कारण से कुटीर उद्योग और बुनकर उद्योग से जुड़े श्रमिक बड़ी संख्या में बेरोजगार हो सरकारी कार्यों पर अपने जीवन निर्वाह के लिए आश्रित हो गये. बदायूं के निम्न जाति के बुनकर लोग, इलाहाबाद के कारीगर, पुनवारी, राट के कारीगर श्रमिक, झाँसी के बुनकर, हमीरपुर के कारीगर, मुरादाबाद के जुलाहा, आदि को उदहारण के तौर पर यहाँ लिए जा सकता है जिनको सरकार इन उद्योगों को संरक्षित करने और इनसे जुड़े श्रमिक के सहायता हेतु कोई राशि प्राप्त नही हुई और उन्हें सरकार के नकरात्मक रवैये के कारण कृषि क्षेत्रों में कठिन कार्यों करने पड़े और सरकारी रिपोर्ट में इन अकुशल श्रमिक कहा गया. सरकार द्वारा औसतन निर्धारित कार्यों से कम कार्य करने के कारण सरकार को अधिक भुगतान करना पड़ा. वास्तव में ये श्रमिक अकुशल नही थे बल्कि अपने क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल थी. फतेहपुर में इसके विपरीत चमड़े के बैग की मांग पानी को संचित करने के कारण दुगना बढ़ गया लेकिन इसके बारे में हमें अधिक जानकारी इस दस्तावेज से नही प्राप्त होती है.

अलग अलग जिलों में खाद्यान के अलग-अलग मूल्य और उनके कीमत में बढ़ोतरी, केंद्रीय प्रशासन का इन मूल्यों को नियंत्रित करने में विफलता, विकट परिस्थितियों के लिए अनाज भण्डारण की असफलता, बिचौलियों और साहूकारों के द्वारा लाभ (जिनमें यूरोपीय भी शामिल) और लोगों को उचित कीमत पर अनाजों को उपलब्ध न होने का वाकया भी हमें इस दस्तावेज में कई जगह देखने को मिलता है. इसके कारण एक और तो लोग कमल के जड़ो, पत्तों, पेड़ों की छाल पर अपने जीवन गुजारने के लिए निर्भर होना पड़ा तो दूसरी और जो इस समस्या से नही जूझ पाए भोजन की कमी और बीमारियों के कारण मौत के मुंह में समा गये.

बड़ी संख्या में कृषि और परिवहन के लिए उपयोगी पशु चारे की अनुपब्धता और उचित सरकारी सहायता के बिना या तो कम दामों में कृषकों के द्वारा बेच दिए गये या मारे गये. इस विकट और आपदा भरे समय में सबसे ज्यादा नुकसान कृषक समाज को उठाना पड़ा. इस समय इन समस्या ने निपटने ममें ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण पशु संसाधन की कमी के कारण समाज में पशुओं की चोरी जैसे मुद्दों की संख्या काफी बढ़ गयी थी.[10] सरकार का इस संदर्भ में बिजनौर में मात्र 30 रूपए की सरकारी सहायता उनकी मंशा को उजागर करता है. महोबा में कुल पशुओं के 20 प्रतिशत, हमीरपुर में 75% के मर जाने से 50000 एकड़ कृषि जोत में कमी आई. ऐसे वाकये हमें प्रान्त के हरेक संभाग में देखने को मिलता है. पशुओं से जुड़े रोगों जैसे काऊ पॉक्स, बाँदा फुट का जिक्र और पशुओं के भारी संख्या में मरने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का जिक्र भी हमें इस दस्तावेज से प्राप्त होता है. इसके आर्थिक परिणाम पर गौर करें तो एक तो बड़ी संख्या में जमीन का परती रह जाना और साहूकार द्वारा प्रदत ऋण के द्वारा पशुओं, बीजों की खरीद ने इनके भविष्य को और अंधकार में डाल दिया. सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली तकावी ऋण (3 वर्षों में बिना सूद के वापसी) पर गौर करें तो इसके प्रावधान में भूसम्पत्ति के मालिकों की अनुमति के नियत होने से एक ओर तो भूमिहीन वर्ग और मालिकाना हक़ के बिना कार्यरत किसान इससे बाहर हो गए तो दूसरी ओर इसके कारण इसका लाभ समाज के प्रभुत्वशाली और जमींदार वर्ग को मिला और समाज के निचले तबके के लोग इस लाभ से वंचित हो गये.

1857 की क्रांति में भागीदार जिलों झाँसी में सरकारी सहायता काफी कम थी. दिल्ली से छपने वाले समाचार पत्रों में इस क्षेत्र के प्रति नकारत्मक सोच हमें देखने को मिलता है. एक विभेदीकृत चित्र के रूप में आकाल हमें क्लिष्ट सामाजिक संरचना से परिचित कराता है. पहली श्रेणी में शामिल काशीपुर, मांडके राजा, जमींदार, रैयत समाज के सम्मानित व्यक्ति तो दूसरी तरफ समाज के उपश्रित लोगों को इस आकाल में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. एक सीमा तक प्रथम श्रेणी ने अपने साक्षरता, सरकार से जुडाव, उभरते हुए मध्य वर्ग से संपर्क और राष्टवाद के उभरते हुए स्वरुप का फायदा उठते हुए मालगुजारी में छुट, तकावी ऋण और प्रार्थनाओं द्वारा ब्रिटिश हुकूमत से अपने कुछ हकों को प्राप्त करने में सफल हुए. दो दूसरी श्रेणी को ये सुविधा नहीं उपलब्ध होने के कारन शोषण का शिकार होना लाज़मी था. रोहेलखंड के पुअर हाउस में महिलाओं और बच्चों की संख्या हमें पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलती है जिसका मुख्य कारण मजदूरी का काफी कम होना था साथ ही यह पुरुषों का दूसरे शहर में रोजगार के लिए पलायन को भी संदर्भित करता है.[11] वहीं दूसरी ओर समाज के उच्च तबकों की संख्या काफी कम दिखती है एवं महोबा और लाट में जहाँ मुस्लिम, कोइरी और ब्राह्मण थे वहां अन्य पुअर हाउस के विपरीत हमें बिना पकाए हुए भोजन के प्रबंधन हमें 'पवित्र और अपवित्र'[12] के विचारों से परिचित कराता है. अजमेर में प्रवासी माड़वारियों मेरठ में राजपूतना के प्रवासी, मुज्जफरनगर में बीकानेर के प्रवासी, आगरा में जयपुर, टोंक, धौलपुर के प्रवासियों एवं मिर्ज़ापुर के सोन से सटे पहाड़ी लोग (जंगल पर आश्रित) के द्वारा श्रमिक के रूप में कार्य करने से मना करने और इनमें से कुछ जिसमें पर्दानशीन कुलीन महिलाएं शामिल थी को निजी सहायता उपलब्ध कराया जाना कुछ खास वर्गों के लिए विशेष सहायता के उपलब्ध होने का संकेत करता है, जिससे समाज के निम्न तबके वंचित थे.

इस प्रकार हम कह सकते है की मानव जनित आपदा में राज की नीतियाँ जिम्मेदार थी.

औपनिवेशिक सरकार भुखमरी और अकालों से उत्पन्न समस्या से निपटने में विफल रही. शासित के नज़रों में खुद को वैध साबित करने के लिए उनके द्वारा जो संविदात्मक मानव्परोप्कारी कार्य की शुरुआत जी गयी उसका जमीनी सर्कोअर और आम जन के भालाई से लेना कम ही था. ब्रिटिश रणनीतिक नैतिक उद्देश्य की की पूर्ति और शासित को बुरे वक्त से निकलने के लिए निर्मित नहीं की गयी थी बल्कि उस समय के राजनितिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक परिद्रश्य में उनके हितों की पूर्ति और सम्रजिक दाद्न्चों को मज़ुबुत बनाने से जुडी थी.

References

1. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869 एंड द बिगनिंग ऑफ़ 1870*, पेज1, इस रिपोर्ट में 1868-1869 से पहले के मुख्य आकालों और सूखा 1803, 1837-1838, 1860-1861, का जिक्र किया गया है.
2. माइक डेविस, लेट विक्टोरियन होलोकास्ट: एलनीनो फैमिन्स एंड मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, वर्सो. 2017.
3. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन में दिए गये व्याख्यानों ' द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया' (1870), और पावर्टी ऑफ इंडिया(1873),
4. तीर्थंकर रॉय, रूट्स ऑफ एग्रे रियन क्राइसिस इन इंटरवॉर इंडिया: रिट्रीविंग नैरेटिव, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 2006, *41(54), 5389–400*
5. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869,* एपेंडिक्स *IV*, पेज. *xxv*, कच्चे कुओं के निर्माण का लागत 5 से २५ रूपये के बीच था. अपने कम लागत और आकाल के समय कुछ बीघा सिंचाई से इसकी लागत उसूल हो जाती थी.
6. उपरोक्त पेज. *2*, 1865 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रान्त की कुल जनसँख्या 30 मिलियन और इसमें से लगभग 7.5 मिलियन लोग उद्योगों, खेतिहर और दैनिक भत्ते पर काम करने वाले मजदूर थे.
7. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869,* पेज नंबर, 99-103, यहाँ हम यह भी देख सकते हैं की विभिन्न जिलों में अलग अलग मजदूरी दरों के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट में 1000 क्यूबिक फिट की खुदाई की मजदूरी में भी अंतर था.
8. उपरोक्त पेज. *24*, एफ. डब्लू. ट्विग ने यहाँ जिक्र किया की काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार का अवसर सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया. जिनमें से *4/5* लोगो अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र से संदर्भ रखते थे.सरकार के द्वारा पअर हाउस का ग्रामीण अंचलों से दूर होना मजदूरी की दरों का कम होना आदि अनेक कारण थे परन्तु श्रम की उपलब्धता उन्हें इस विकार समय में जीने का अवसर प्रदान कर सकती थी, जिसमें नैतिक, उदारवादी मने जाने में राज के शासन की असफलता और निरंकुश होने को सूचित करती है.
9. अमर्त्य सेन, पोवेर्टी एंड फेमिंस: एन एस्से ऑनएंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन, ऑक्सफ़ोर्ड: लन्दन, 1981. सेन इस संदर्भ में कहते हैं की अधिकतर आकाल के समय खाद्यान आपूर्ति में कमी नही आई बल्कि इसके लिए कई समाजिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार थे जैसे, मजदूरी की घटती दर, बेरोजगारी, खाद्यान के बढ़ते मूल्य, और भोज्य पदार्थों के वितरण की असमुचित व्यवस्था.
10. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869*. पेज 127. इस संदर्भ में उपलब्ध

जानकारी पर गौर करें तो कृषिगत कार्य के लिए उपयोगी पशुओं की चोरी *1867* में *10,218* थी, जो *1868* में *12,196*, अन्य प्रकार जैसे डकेती की संख्या इस काल में *57* से बढ़ के *122*, एवं 1870 में इन चोरियों की संख्या *18,699* से बढ़ कर *32,090* हो गयी.

11. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869,* पेज.*31* और पेज *76*. पुअर हाउस में महिलाओं और बच्चों की संख्या *76%* यहं पुरुषों का कम होना सूचित करता है.एवं परुषों इस आकाल और सूखा जैसा मानव जनित आपदा के कारन खरीफ फसल के नष्ट होने के बाद मालवा जाने का उदाहरण यहाँ लिया जा सकता है.
12. फेड्रिक हेन्वी *"ए नैरेटिव ऑफ़ द ड्राउट एंड फेमीन इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1868-1869,* पेज.*70*, श्रम के बंटवारे का सामजिक आधार यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ उच्च जातियों के द्वारा भोजन बनाये जाने वहीँ बुनकरों के द्वारा वस्त्रो की कताई और बनाई का उल्लेख यहाँ मिलता है.